(d) As per 1971 Census, 32,916 villages have been electrified in Orissa by the end of June, 1994.

एन०टी०पी०सी० और राज्य बिजली बोर्डों के बीच विवाद

1058. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों के बिजली बोर्डों और एन०टी०पी०सी० के बीच गंभीर विवाद पैदा हो जाने के कारण संपूर्ण उत्तर भारत में अभूतपूर्व विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, उन राज्यों के नाम क्या हैं जो उक्त विवाद में शामिल हैं और इस विवाद का मुख्य कारण क्या है और इन दो पक्षों के विवाद से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई तात्कालिक और प्रभावी कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Hike in Power Tariff

1059. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether a steep hike in power tariff is imminent as has been hinted by him while recently addressing Joint Indo-US Commission on energy; and

(b) if so, by when it is likely to come into force?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) The tariff for sale of electricity to the different sectors of consumers is fixed by the SEBs themselves, with the approval of the State Governments concerned. The Power Ministers' Conference held in January, 1993 has adopted an Action Plan which provides for periodical revision of all tariffs, taking into account the increased cost of production and supply.

Capacity Utilisation in Thermal and Hydel Power Plants

1060. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the targets set and achievements made in both Thermal and Hydel power Plants during the last three years;

(b) what are the reasons for low capacity utilisation; and

(c) the steps taken to improve Plant Load Factor (PLF) by State Electricity Boards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Energy Generation Targets vis-a-vis actual generation from thermal and hydel power stat-

ons during 1991-92 to 1993-94 are given below :—

(Figures in MU)

Year	Target	Actual
1991-92		
Thermal	211700	208551
Hydel	64900	72599
1992-93		
Thermal	229050	224485
Hydel	66300	69833
1993-94		
Thermal	243200	247618
Hydel	67500	70311

(b) The reasons for low capacity utilisation include following :—

(a) declining quality of coal;

(b) resource constraint;

(c) lack of trained manpower etc.;

(d) High rate of forced outages;

(e) long time taken in maintenance/ recovery from forced outages;

(f) delay in procurement of spares;

(g) defective maintenance and/or operation;

Capacity utilisation of Hydro-electric units depends on level of water in reservoirs.

(c) Various measures taken to improve the performance of TPSs in the country are — Renovation and Modernisation of old units, assistance to Electricity Boards in undertaking Plant Betterment Programmes, supply of requisite quantity and quality of coal, award schemes for better performance, and for efficient & economic operation of stations and traintng of operation & maintenance of personnel etc.

विद्युत क्षेत्र में अमरीका के साथ समझौते

1061. श्री वी. हनुमंत राव :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में अमरीका और अन्य अनेक अमरीकी फर्मों के साथ कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कौनसे क्षेत्र हैं जिनको इससे लाभ होगा और प्रत्येक क्षेत्र को इस प्रकार होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है; और

(ग) इन समझौतों के अनुसार काम कब प्रारंभ होगा और पहली ऐसी इकाई कब तक चालू हो जाएगी और इन समझौतों के अंतर्गत कुल कितनी बिजली उत्पन्न की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में यूएसए के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तथापि निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अमरीका अवस्थित 22 फर्मों ने अपनी रुचि प्रकट की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना के लिए विभिन्न निवेश सुनिश्चित करने और वित्त व्यवस्था करने के उपरांत ही इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा। कुछ परियोजनायें आठवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1997 में चालू की जा सकती हैं और शेष 9वीं योजना में चालू की जा सकती हैं।